श्री अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल

न डॉक्टर हैं न साजो सामान, इलाज करा लो, इलाज करा लो

छांयसा (म.मो.) खट्टर सरकार बीते दो साल से छांयसा के गांव मोठुका स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चलाने के दावे लगातार करती आ रही है। बीते करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दिखावे के लिये फौजी मेडिकल स्टॉफ़ भी तैनात कर दिया गया था। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिये तमाम स्थानीय सत्तारूढ़ सांसद, विधायक, मंत्री आदि ने यहां हवन आदि का ढोंग करके अस्पताल को चालू घोषित कर दिया था। परन्तु ड्रामा तो ड्रामा ही होता है, सो कुछ दिन चलने के बाद टांय-टांय फिस हो गया।

इस महीने फ़िर से सरकार ने इस अस्पताल की केवल ओपीडी चालू करने की बात कही है। ओपीडी यानी मरीज़ आयें, डॉक्टर को दिखायें, आवश्यक जांच आदि करायें और दवा लेकर घर जायें। इसमें मरीज़ को भर्ती नहीं किया जाता। किसी भी अस्पताल में सर्वप्रथम जरूरी कैजुअल्टी विभाग यानी जहां कोई भी मरीज़ आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा ले सके, उसकी व्यवस्था यहां नही है। दूसरे नम्बर पर आता है प्रसूति विभाग यानी जहां गर्भवती महिलाओं की डिलिवरी हो सके, वह भी यहां नदारद है। जहां ये दोनों चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध न हों तो उसे अस्पताल कैसे कहा जा सकता है और वो भी 'श्री अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल'?

सबसे अधिक रोगी मेडिसिन विभाग के आते हैं जिसका कोई डॉक्टर यहां मौजूद नहीं है। किसी की हड्डी-पसली टूट जाये तो उसकी जांच करने के लिये यहां एक्सरे मशीन तक भी नहीं है। इसके अभाव में हड्डी सम्बन्धित कोई इलाज नहीं हो सकता। एमआरआई व सिटी स्कैन जैसे उपकरणों की बात तो छोड़ ही दीजिये रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर व रेडियोग्राफ़र तक यहां नहीं है। खून व मल-मूत्र आदि की जांच के लिये भी यहां कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिये मरीज़ों को बीके अस्पताल रेफ़र किया जाता है जो खुद अपने मरीजों की जांच अस्पताल के बाहर दुकान सजाये बैठे लैबोरेट्री वालों से कराते हैं।

ऑपरेशन थियेटर की तो यहां जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑपरेशन के बाद मरीज़ को भर्ती करना पड़ता है। जिससे इन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर लिये हैं। प्रोपेगेंडे के तौर पर 10 रुपये में कैंसर का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां रेडियो थेरेपी से कैंसर का इलाज किया जायेगा। यह मात्र प्रोपेगेंडा है।

रेडियो थेरेपी के लिये जो आवश्यक उपकरण होने चाहिये वो यहां नहीं है। इनके पास है तो केवल एक डॉक्टर जो कैंसर के इलाज बाबत कुछ जानते हैं लेकिन वे भी आवश्यक उपकरणों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते।

प्रोपेगेंडे के तौर पर इस संस्थान के डायरेक्टर गौतम गोले आसपास के 26 गांवों में पूरे जोर-शोर से प्रचार करके इलाज के लिये लोगों को अपने यहां आमंत्रित कर रहें है। लेकिन प्रचार क्या करेगा जब वहां सौदा ही कुछ न हो तो? दिन भर में भूले-भटके बमुश्किल 10-20 लोग ही यहां आते जरूर हैं लेकिन लौटते खाली हाथ हैं। इन लोगों का ही मौखिक प्रचार पूरे देहात में ज्यादा असरकारी होता है। इसलिये फिजूल में यहां धक्के खाने कौन और क्यों आये?

गौरतलब है कि इसी अस्पताल में, जब ये प्राइवेट था, करीब दो हजार मरीज़ रोजाना ओपीडी में आते थे। इन्हीं में से जरूरतमंद मरीज़ों को भर्ती भी किया जाता था। अस्पताल के कुल 300 में से 200 बेड भरे रहते थे। बतौर फेकल्टी जो डॉक्टर भर्ती कर रखे हैं वे भी दुखी हैं। करने को कोई काम नहीं और उठने-बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं। कुछ डॉक्टरों ने तो अपने पल्ले से खरीद कर एसी तक लगवाये हैं। इस सबके बावजूद कैदियों की तरह उनकी हाजरी पर डायरेक्टर का ज्यादा ध्यान रहता है।

हरियाणवी कहावत यहां बहुत सटीक बैठती है

गांव की गली में पलंग बेचने वाला एक व्यक्ति आवाज़ लगा रहा था, 'पलंग ले लो पलंग ले लो, चार नहीं है पाये, दो नहीं है बाही और एक नहीं है सेरू, पलंग ले लो पलंग ले लो'।

हरियाणवी समझने वाले खट्टर भाई तो समझ गये होंगे कि उनका अटल बिहारी अस्पताल ठीक उस पलंग बेचने वाले जैसा ही है जो केवल एक सेरू हाथ में लिये पलंग बेचने का हल्ला कर रहा है।

विदित है कि पलंग में दो बाही, दो सेरू व चार पाये होते हैं जबकि इस पलंग बेचने वाले के पास केवल एक सेरू ही है जिसे वह पलंग बता कर बेचना चाह रहा है।

डॉक्टरों को परेशान करके आनंदित होते हैं ईएसआई कोर्पोरेशन के मेडिकल कमिश्नर दीपक शर्मा

फ़रीदाबाद (म.मो.) ईएसआई कोर्पोरेशन के दिल्ली स्थित मुख्यालय में तैनात मेडिकल कमिश्नर दीपक शर्मा को यह अधिकार है कि वे कार्पोरेशन के डॉक्टरों को देश के किसी भी ईएसआई अस्पताल में नियुक्ति पर भेज सकते हैं। अपने इस अधिकार का प्रयोग वे मरीज़ों तथा डॉक्टरों की भलाई में न करके केवल अपनी अहंकार को संतुष्ट करने के लिये करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि दक्षिण भारत का डॉक्टर उत्तर में व उत्तर भारत का डॉक्टर दक्षिण के मरीज़ों के साथ कैसे तारतम्य बना पायेगा?

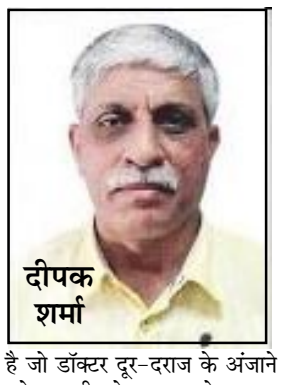

दीपक शर्मा

इसके अलावा हजारों मील दूर जाकर बेहतर सेवायें दे पायेगा अथवा अपने क्षेत्र में रहकर? जाहिर है जो डॉक्टर दूर-दराज के अंजाने क्षेत्र में तैनाती पायेगा उसका ध्यान काम की अपेक्षा अपने घर की ओर ज्यादा रहेगा। वह हर तरह से छुट्टियां लेकर या काम से गैरहाजिर होकर भागने की फ़िराक में रहेगा। ऐसे में असली नुक्सान तो मरीज़ों को ही भुगतना पड़ेगा।

अभी हाल ही में ईएसआई के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस पास करके जो डॉक्टर निकले हैं उनका कॉर्पोरेशन के साथ अनुबंध है कि वे एक साल तक उनके अस्पतालों में नौकरी करेंगे। इसी अनुबंध से बंधे ये युवा डॉक्टर दूर-दराज के इलाकों में नौकरी करने को मजबूर हैं। कहने की जरूरत नहीं कि मजबूरी में कोई काम करता है तो वह कैसा करता है।

यों तो ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट लंबी है लेकिन खोज-बीन करने पर ऐसे कुछ डॉक्टरों की उपलब्ध हुई सूची इस प्रकार है।

डॉ.ननीश कुमार ईएसआई मेडिकल कॉलेज कोलकाता से भेजे गये गुजरात के अंकलेश्वर, डॉ. सरीराज बंगलोर के मेडिकल कॉलेज से गुजरात के अंकलेश्वर, डॉ. नवीन कोलकाता से अंकलेश्वर, डॉ. सचिन फरीदाबाद से नरौदा गुजरात, डॉ. प्रतीक फ़रीदाबाद से आंगुल ओडीसा। डॉ. चन्द्रशेखर गुलबर्गा से बद्दी हिमाचल प्रदेश, डॉ. शिवा प्रिया बैंगलोर से लुधियाना, डॉ. भरथ कुमार चेन्नई से फ़रीदाबाद, डॉ. सर्वेसरा नंद चेन्नई से फ़रीदाबाद, डॉ. पंकज फ़रीदाबाद से अंकलेश्वर।

स्पष्ट है कि जो युवा डॉ. हाल ही में प्रशिक्षित होकर निकले हैं और जिन्हें अभी काम सीखने व करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये, इसकी अपेक्षा वे अपने तबादले अथवा मजबूरी के चलते टाईमपास करने के चक्कर में ज्यादा रहेंगे।

बुढ़ापा पेंशन हड़पने के बाद दिव्यांग बजट पर सरकार की गिद्ध दृष्टि

फ़रीदाबाद (म.मो.) सबसे पहले घरेलू गैस सब्सिडी हड़पने के बाद रेल यात्रा में बुजुर्गों को मिलने वाली सब्सिडी हड़पी। उसके बाद उन बुजुर्गों की पेंशन डकारी जिनके घर में कोई कमाने वाले मौजूद हैं। अब लुटेरी सरकार की गिद्ध दृष्टि दिव्यांगों को मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं पर है।

जुमलेबाज़ी में माहिर भारतीय जुमला पार्टी के प्रधानमंत्री ने विकलांगों को नया जुमला दिव्यांग तो दे दिया। लेकिन अब इन दिव्यांगों की जेब काटने की पूरी तैयारी चल रही है। बीते बीसियों वर्ष से विकलांगता प्रमाणपत्र लिये हुए लोगों से कहा जा रहा है कि 31 अगस्त तक पुन: अपनी विकलांगता का प्रमाणपत्र लेने के लिये अस्पतालों के चक्कर लगायें, वर्ना पहली सितम्बर से उन्हें मिलने वाले वे सब लाभ बंद कर दिये जायेंगे जो उन्हें विकलांगता के आधार पर सरकार से मिलते हैं।

लोगों की सुख-सुविधाओं को हड़पने का कोई मौका न छोड़ने की ताक में रहने वाली भाजपा की खट्टर सरकार ने अपनी इस षड़यंत्र के पीछे यूडीआईडी बनाने का तर्क दिया है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यूडीआईडी पहचानपत्र बनने के बाद विकलांगों को बहुत अधिक लाभ एवं सुविधायें मिलने लगेंगी। दरअसल यह तो केवल एक बहाना है, इसके पिछे असल मकसद तो विकलांगों पर खर्च होने वाले बजट को घटाना है। यदि सरकार की नीयत नेक होती तो यही यूडीआईडी कार्ड विकलांगों को चक्कर कटाये बगैर भी बनाये जा सकते थे।

निर्धारित समय सीमा के भीतर-भीतर दोबारा से सम्बन्धित डॉक्टरों के सामने पेश होकर विकलांगता का प्रमाणपत्र बनाने के लिये सैंकड़ों की संख्या में स्थानीय बीके अस्पताल तथा इसी प्रकार हर ज़िले के

अस्पताल में विकलांग धक्के खा रहे हैं। इसके लिये सबसे पहले तो उन्हें 10 रुपये खर्च करके ओपीडी कार्ड बनवाने के लिये लम्बी कतार में लगना होता है। उसके बाद फार्म जमा कराने के लिये एक अन्य लाइन में लगना होता है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब नम्बर आता है तो काऊंटर पर बैठा बाबू कहता है कि आज जितने फ़ार्म लेने थे ले लिये बाकी कल आना।

उसके बाद जैसे-तैसे सम्बन्धित डॉक्टर के पास जाने का नम्बर आता है तो वहां भी लम्बी लाइन लगी होती है। लम्बे इन्तजार के बाद जब नम्बर आता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज का कोटा जो 30 लोगों का था वो पूरा हो गया, अब अगले हफ्ते आना। विदित है कि अस्पताल में इस काम के लिये केवल बुद्ध तथा शुक्रवार ही रखे गये हैं। ऐसे में कई अंजान विकलांग जो अन्य कार्य दिवसों पर पहुंच जाते हैं उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है।

इसके अलावा आज कल ऑनलाइन के नाम पर भी विकलांगों के साथ काफ़ी क्रुर मजाक किया जा रहा है। ऑनलाइन की यह व्यवस्था बनाई तो इसलिये गई थी कि किसी को भी घर से बाहर चक्कर न काटने पड़े, घर बैठे-बैठे ही ऑनलाईन अपना आवेदन भेज सकें। अब्बल तो 90 प्रतिशत लोगों के घरों में यह सुविधा होती नहीं है, इसके लिये उन्हें पैसे खर्च करके किसी साइबर कैफे की सेवा लेनी पड़ती है। दूसरा भयंकर मजाक यह होता है कि विकलांग अपनी सभी दस्तावेज फोटो-कॉपी अस्पताल में जमा कराये।

पुराने विकलांगों के साथ-साथ नये विकलांग भी प्रमाणपत्र बनवाने को अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जाहिर है इसके चलते काम का बोझ कई गुणा बढ़ जाता है। डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ़ की भारी कमी के चलते, यदि डॉक्टर अपने तमाम अन्य कामों को छोड़कर, जो कि सम्भव नहीं है, केवल विकलांगों का ही काम करता रहे तो भी इस काम को निपटा पाना आसान नहीं है। दरअसल सरकार भी नहीं चाहती कि लोगों के काम आसानी से निपट जायें, वर्ना क्या सरकार को वस्तु स्थिति का ज्ञान नही है? सरकार को क्या मालूम नहीं कि अंधे, बहरे, लंगड़े, लूलों के लिये इस तरह से चक्कर लगाना कितना दुखदायी होता है? सरकार चाहती है कि जनता को इन्हीं चक्करों में ब्यस्त रखा जाये ताकी वे किसी प्रकार की जागरूकता प्राप्त करने की सोच भी न सके।

नई आईडी बनवाने का असल मकसद विकलांगों की विकलांगता का दर्जा घटाकर उनको मिलने वाले आर्थिक लाभों को घटाना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार धीरज जो पहले 100 प्रतिशत विकलांग था उसे 80 प्रतिशत कर दिया जिसके चलते उसका बस व रेल पास और फैमिली पेंशन समाप्त कर दी गयी।

सूरज सुपुत्र श्री रमेश चंद जो पहले 70 प्रतिशत विकलांग था उसे घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया।

देखो विकलांगों के भी अच्छे दिन आ गये न।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।